



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

म्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—लेण्ड 3—उपलेण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 174]

नई दिल्ली, इनिवार, मई 18, 1968/वैशाख 28, 1890

No. 174]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 18, 1968/VAISAKHA 28, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दे जाती है जिससे यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF COMMERCE

## ORDER

New Delhi the 18th May 1968

S.O. 1758.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following amendment in the order of the Government of India in the Ministry of Commerce, S.O. No. 1844 dated the 18th June, 1968, namely:—

In the said Order, after condition (iii) of the direction contained in paragraph (a), the following condition shall be inserted, namely:—

“(iv) that in making an Order relating to any of the matters specified in clause (j), the State Government or, as the case may be, the administrator of a Union Territory shall authorise only an officer of Government.”

[No. 26(17)-CS.II/66.]  
B. N. BANERJI, Spl. Secy.

वाणिज्य संचालन

आदेश

नई दिल्ली, 18 मई 1968

एस. एस. 1759.—प्रत्यावर्तक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 को द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एवं द्वारा भारत सरकार के वाणिज्य

नवालय के एप्र० ग्रो० सं० 1844 दिनांक 18 जून, 1965 के आदेश में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उपर्युक्त आदेश के नं० ८ (८) में दिये गये नियम की शर्त (३) के पश्चात् निम्नलिखित शर्त निषिद्ध की जायेगी, अर्थात् :—

“(४) कि भारा (व) में उल्लिखित किसी भी मासले से सम्बन्धित आदेश देते समय राज्य सरकार अथवा जैसी दशा हो, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन सरकार के किसी अधिकारी को ही प्राधिकरण करेंगा।”

[सं० 26 (१) सं० एप्र०-२/६६-]

मी० एन० बनर्जी, विशेष सचिव ।